सं. जी- 11014/4/2013- एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान

******

12वां तल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली - 110003 दिनांक 2 जुलाई, 2014
दूरभाष सं. 011-24364427 फैक्स: 24361062/24364869

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव
सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

विषय: एनबीए आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रविष्टि, 2013- त्वरित गति से होती प्रगति

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के दिनांक 18/6/2014 के समसंख्यक पत्र की ओर कृपया ध्यान दें, जिसमें आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए वित्तीय प्रावधान के विषय में राज्यों को सूचित किया गया है । इसके पश्चात इस कार्यालय के दिनांक 9 जून. 2014 के पत्र के माध्यम से राज्यों को प्रविष्टि की प्रक्रिया शुरू करने तथा उसे 31 जुलाई, 2013 तक पूरा करने को कहा गया था । दोनों पत्र इस मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

2. आज दिनाक 2 जुलाई, 2014 को इस मंत्रालय द्वारा एमआईएस (आधारभूत सर्वेक्षण तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) दोनों) पर आकड़ों की प्रविष्टियाँ करने के संबंध में राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई । समीक्षा करने पर पाया गया कि आधारभूत सर्वेक्षण के संबंध में केवल 16.24 लाख पारिवारिक आंकड़ों तथा 1.42 लाख आईएचएचएल वास्तविक उपलब्धि संबंधी आंकड़ों की सूचना एमआईएस पर डाली गई है । (राज्यवार विवरण संलग्न है)

3. जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवारों की संख्या बहुत अधिक (17.19 करोड़) है, जिन्हें एमआईएस पर डाला जाना है । इसके अतिरिक्त, नई सरकार के 100 दिनों के कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत सरकार एनबीए के अंतर्गत विभिन्न घटकों के कवरेज पर राज्यों की उपलब्धियों का अनुवीक्षण भी करती है । इस संबंध में दिनांक 2.7.2014 तक प्राप्त सूचना के अनुसार उपलब्धिया सतोषजनक नहीं हैं ।

4. अत: आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि कार्यक्रम के सभी घटकों में इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तत्काल व्यवस्था करें तथा उच्च प्राथमिकता के आधार पर एमआईएस पर उसे सूचित करें । यह अपेक्षित है कि जून 2014, की प्रगति की रिपोर्ट, जिसे 15 जुलाई, 2014 को समेकित किया जाएगा, में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण तथा एमपीआर के अंतर्गत वास्तविक प्रगति के आंकड़ें दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होगी ।

5. तथापि, यह संकेत किया जाता है कि अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने एमपीआर के आंकड़ों की प्रविष्टि शुरू तक नहीं की है या आंकड़ों की प्रविष्टियां बहुत कम हैं ।

इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ।

संलग्नक : यथोक्त

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक, एनबीए

प्रति :

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य एनबीए समन्वयकर्ता